सं. 1(2)/2025-समन्वय

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

******

अगस्त, 2025 माह के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) का मासिक सारांश

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय: -

वर्ष 2025-26 के लिए अगस्त, 2025 के अंत तक चुनिंदा सीपीएसई (जिनका वार्षिक पूंजीगत व्यय अनुमान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का है) और अन्य सरकारी संगठनों (रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और दामोदर घाटी निगम) के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्धि की जानकारी संकलित की गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन संस्थाओं ने 2.72 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हासिल किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट अनुमान का 34.70 प्रतिशत है।

2. सीपीएसई का संचालन: -

(i) डीपीई ने 31 जुलाई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) में बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर 7 पदों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भेजी।

(ii) डीपीई ने 08 अगस्त, 2025 को नवरत्न का दर्जा देने के संबंध में एसईसीआई को प्रत्यायोजित बढ़ी हुई शक्ति के प्रयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर अपनी टिप्पणियां भेजीं।

(iii) महारत्न और नवरत्न सीपीएसई की व्यापक समीक्षा और अनुसूची क/ख/ग/घ वर्गीकरण दिशानिर्देशों पर शीर्ष समिति की बैठक 13 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई।

3. समझौता ज्ञापन- सीपीएसई का कार्य निष्पादन मूल्यांकन:

वर्ष 2024-25 के लिए: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं की उपलब्धता के बाद अक्टूबर, 2025 में शुरू होगा।
वर्ष 2025-26 के लिए: वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में, 86 सीपीएसई के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया। जिनमें से 83 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स: -

(i) अगस्त, 2025 माह के दौरान अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की 01 बैठक में भाग लिया गया।
(ii) अगस्त, 2025 माह के दौरान अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 01 बैठक में भाग लिया गया।

5. क्षमता निर्माण: -

(i) डीपीई ने 22 अगस्त, 2025 को दक्षिण और पश्चिम भारत में स्थित सीपीएसई के लिए मुंबई में उद्योग 4.0 पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें सीपीएसई के वरिष्ठ कार्यपालकों (सीएमडी और निदेशकों) सहित लगभग 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तनकारी उत्पादकता, दक्षता और नवाचार लाने में उभरती उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। सचिव, डीपीई और विशेषज्ञों ने एआई, डिजिटल ट्विन, 3डी प्रिंटिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकियों तथा उद्योगों में परिवर्तन लाने और सीपीएसई के लिए भावी राह में इन प्रौद्योगिकियों की भूमिका के बारे में बताया।

(ii) डीपीई के 83 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने अगस्त, 2025 तक आई-गॉट पोर्टल पर 3,171 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

(iii) डीपीई के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, डीपीई के 4 अधिकारियों ने सीपीएसई के कामकाज के साथ एनएचपीसी लिमिटेड का अनुभव-ग्रहण दौरा किया।

6. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ

(i) अगस्त, 2025 माह के दौरान सीपीएसई/एसएलपीई के अधिकारियों के लिए डीपीई द्वारा आयोजित 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का विवरण।

7. एमएसई से खरीद: -

एमएसई से सीपीएसई द्वारा अब तक की कुल 70,402 करोड़ रुपये की खरीद में से लगभग 29,824 करोड़ रुपये की खरीद कर ली है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद क्रमशः 1,177 करोड़ रुपये और 2,008 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति: -

दिनांक 01.09.2025 तक, एएमआरसीडी डैशबोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, पोर्टल पर 218 मामले दर्ज किए गए हैं। वित्तीय सलाहकार के स्तर पर 53 मामलों को खारिज कर दिया गया। 55 मामलों का निपटान किया गया है और 93 मामले सचिवों की समिति के पास निर्णयाधीन हैं। शेष 17 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी जांच और अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

*****